22.3 of the Modifications in Drug Policy, 1986, issued in 1994.

(ii) To encourage investment in and production of these drugs in the country for having lower prices and to reduce imports.

(iii) Stopage of production of these drugs by M/s IDPL.

निगमों को दी जाने वाली खाद्यान्नों संबंधी राजसहायता

*78. **श्री लक्खीराम अग्रवाल:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम और अन्य निगमों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित रियायती दरों पर आपूर्ति किए गए गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल इत्यादि पर वर्षवार और मदवार कितनी-कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या गेहूं, चावल और चीनी आदि के मूल्यों में वृद्धि के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को भारतीय खाद्य निगम को अपेक्षाकृत कम राजसहायता देनी पड़ेगी; और

(ग) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम आदि को अपने अनावश्यक खर्चे कम करने के लिए कहेगी या ऐसे खर्चों की समीक्षा करेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों और चीनी पर सब्सिडि के प्रति भारतीय खाद्य निगम को तथा खाद्य तेल खाते में कमी की पूर्ति के लिए राज्य व्यापार निगम को निम्नलिखित राशियां निर्मुक्त की गई थीं:—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष (वर्षों)	गेहं और चावल	चीनी	खाद्य तेल
1995-96	4960	422	100
1996-97	5166	900	50
1997-98	7500	400	20

(ख) जी, हां।

(ग) प्रचालनों के विशाल आकार और सब्सिडि की सीमा की दृष्टि में भारतीय खाद्य निगम के प्रचालनों और वहन किए गए खर्च की निरंतर समीक्षा की जाती है। राज्य व्यापार निगम के लिए खाद्य तेल खाते में कमी (i) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आर०बी०डी० पामोलीन के मूल्यों (ii) सीमा शुल्क अवसंचरना और (iii) स्वयं केन्द्रीय निर्गम मूल्य जैसे घटकों के कारण भिन्न-भिन्न रहती है जिसके परिणामस्वरूप तेलों/तिलहनों की स्वदेशी उपलब्धता मूल्य और मांग प्रभावित होते हैं।

पानीपत से कैराना के लिए रेल लाइन

*79. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पानीपत (हरियाणा) से कैराना, मुजफ्फरपुर (उत्तर प्रदेश) तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेल लाइन बिछाने का कार्य कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) कैराना के रास्ते पानीपत और मुजफ्फरनगर के बीच एक नई रेल लाइन के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण 1997-98 के दौरान स्वीकृत किया गया था। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(ख) पानीपत और कैराना के बीच के भाग में फील्ड सर्वेक्षण पूरा हो गया है और शेष भाग में यह प्रगति पर है।

(ग) दिसंबर, 1999 तक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की संभावना है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद ही इस परियोजना पर आगे विचार किया जा सकेगा।

चीनी मिलों का औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकरण

*80. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में 37 चीनी मिलें पंजीकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो मिल-वार प्रत्येक मामले में कब-कब पंजीकरण कराया गया था; और

(ग) मिल-वार प्रत्येक मामले में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ग) 31.1.99 तक की स्थिति के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत रुग्ण चीनी कम्पनियों के 39 मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत किए गए थे। 39 मामलों में से 4 कम्पनियां अलग-अलग समय पर दो बार पंजीकृत की गई थीं। उसे ध्यान में रखते हुए वास्तव में 35 कम्पनियां ही बी०आई०एफ०आर० में पंजीकृत हैं। पंजीकरण की मिलवार तिथि तथा प्रत्येक मामले में हुई प्रगति विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) इस दिशा में हुई प्रगति का सारांश निम्नवत है:—

(क) स्वीकृति पुनरुद्धार योजना	7
(ख) गैर-अनुरक्षणीय के रूप में खारिज	7
(ग) परिचालित ड्रॉफ्ट योजना	1
(घ) बन्द किए जाने की सिफारिश	
(ङ) निरीक्षण के अधीन	8
(च) अब रुग्ण नहीं घोषित	6
कुल	35

31.01.1999 तक बी०आई०एफ०आर० द्वारा इकाईवार पंजीकरण की तिथि और आदेश जारी करने की तिथि तथा इसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	इकाई का नाम	पंजीकरण की तिथि	आदेश की तिथि
1	2	3	4
धारा 18(4) के तहत स्वीकृत पुनरुद्धार योजना			
1.	मेवाड़ शुगर	1.9.87	1.5.95
2.	लक्ष्मी शुगर मिल्स	21.7.89	18.2.94
3.	कानपुर शुगर वर्क्स लि०	3.12.92	23.12.98
4.	शेरवानी शुगर सिंडिकेट लि०	9.2.93	18.10.95
5.	कावेरी शुगर्स तथा केमिकल्स लि०	13.2.96	23.12.97
6.	सराया शुगर मिल्स लि०	21.2.97	10.12.98
7.	श्री कैलाश शुगर्स तथा केमिलकल्स लि०	20.5.97	4.12.98
गैर-अनुरक्षणीय के रूप में खारिज			
1.	कावेरी शुगर्स तथा कैमिकल्स	17.7.87	11.12.87
2.	कानपुर शुगर्स वर्क्स	12.8.87	28.9.87
3.	नवाबगंज शुगर वर्क्स	24.8.87	16.6.89
4.	तुंगभद्रा शुगर वर्क्स	20.11.87	13.7.88
5.	श्री सीताराम शुगर कं०	15.1.88	12.6.89
6.	देवरिया शुगर मिल्स लि०	12.2.88	12.6.89
7.	ब्रिमा शुगर लि०	2.6.88	20.3.90
8.	बेलापुर शुगर तथा एलाइड	2.6.88	31.3.89
9.	रत्ना शुगर मिल्स लि०	22.6.88	28.9.89
10.	नंदगंज सिबोरी शुगर कं० लि०	20.4.95	5.6.95
11.	छाता शुगर कं० लि०	26.4.95	2.6.95

1	2	3	4
	परिचालित ड्रॉप्ट योजना		
1.	नंदगंज सिहोरी शुगर कं० लि०	6.2.96	30.6.97
	धारा 20(1) के तहत बन्द करने की सिफारिश		
1.	चम्पारन शुगर	12.8.87	28.6.93
2.	जिवाजी राव शुगर	8.3.88	18.1.91
3.	सलारजंग शुगर	5.4.88	17.10.96
4.	गंगावती शुगर	30.8.88	29.9.95
5.	स्वदेशी ग्लाइनिंग तथा मेनि० कं० लि०	2.1.95	1.7.96
6.	घाटमपुर शुगर कं० लि०	9.6.95	25.8.98
	निरीक्षण के अधीन		
1.	त्रावणकोर शुगर्स तथा केमिकल्स लि०	20.6.95	30.6.95
2.	उत्तर प्रदेश राज्य शुगर कोर्पो. लि.	20.6.95	—
3.	एच.एम.पी. शुगर्स लि.	11.10.96	—
4.	छाता शुगर क. लि.	16.7.97	—
5.	बी.एस.आई. लि.	17.6.98	—
6.	गिरधारीलाल शुगर तथा एलाइड इंडस्ट्रीज	31.8.98	—
7.	खलीलाबाद शुगर मिल्स प्रा० लि०	13.1.99	—
8.	विक्रम प्रोजेक्टस लि०	21.1.99	—
	अब रुग्ण नहीं घोषित		
1.	चल्लापली शुगर	19.6.87	17.1.96
2.	देवनगेरे शुगर क०	24.8.87	14.2.96
3.	गोदावरी शुगर मिल्स	25.9.87	29.11.94
4.	किरियमपुड शुगर मिल्स	2.11.87	31.3.92
5.	भगवानपुर शुगर मिल्स	24.2.88	27.3.97
6.	रामनुगर केन (खेतान एग्रो कॉम्पलेक्स)	30.5.88	13.9.96

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Gold Plating by Urea Firms

466. SHRI JIBON ROY:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Panel will look into Gold plating by urea firms", which appeared in "The Times of India" of 6th January, 1999;

(b) if so, the present status of recovery of subsidy, with retrospective effect, from the fertilizer companies involved in underrating of name plate capacities;